यू. पी. हिंदी साहित्य सम्मेलन

बनाम

यू. पी. राज्य

(सिविल अपील सं. 459/1997)

सितंबर 04,2014

[आर. एम. लोधा, सीजेआई, दीपक मिश्रा, मदन बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ और एस. ए. बोबडे, न्यायाधिपति]

भारत का संविधान, 1950 - भाग XVII; अनुच्छेद 345 और 347 - संवैधानिक योजना का भाग XVII - अनुच्छेद 345 एवं 347 का दायरा और परिधि - विवेचना की गई।

भारत का संविधान, 1950 - भाग XVII; अनुच्छेद 345 और 347 - 1951 अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों और अन्य मामलों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए अधिनियमित किया गया था - इसके बाद, 1951 अधिनियम में संशोधन करने के लिए 1989 संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उद्देश्यों के लिए उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रदान करने वाले अधिनियम की धारा 2 के बाद धारा 3 को शामिल किया गया था - क्या यह यूपी के लिए संवैधानिक था? विधान सभा ने 1989 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया, जबकि 1951 में अनुच्छेद 345 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था -अभिनिर्धारित : केवल इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया था और इसे राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था,

यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान ने राज्य में उपयोग में आने वाली किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के राज्य विधानमंडल के विकल्प को बंद कर दिया है - अनुच्छेद 345 ने हिंदी के अलावा राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाओं को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने पर प्रतिबंध है - उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में न तो धारा 3 को शामिल किया गया न ही उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में सात निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना असंवैधानिक थी - उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 - धारा 3-उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया : 1.1. केवल इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया है और इसे राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान राज्य में उपयोग में आने वाली किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के राज्य विधानमंडल के विकल्प को बंद कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 345 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदी के अलावा राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाओं को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने पर रोक लगाता हो। [पैरा 26 और 27][693-डी-ई]

1.2. अनुच्छेद 345 में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग बिना महत्व के नहीं है। यह इंगित करता है कि राज्य को राज्य में उपयोग में आने वाली भाषा या भाषाओ को अपनाने में विवेकाधिकार है और साथ ही हिंदी को भी। इस तरह के विवेक का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा जितनी बार उचित समझे उतनी बार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऐसी विधायी शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध अनुच्छेद 347 में है। [पैरा 31][695-डी-ई]

1.3. अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। ये दोनों प्रावधान किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने या निर्देश जारी करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 347 में आवश्यकता, "किसी राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा के उपयोग को उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करने की इच्छा रखता है" अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल के लिए भाषा को अपनाते हुए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य की राजभाषा, जो राज्य में प्रयोग में आती है। अनुच्छेद 347 की मांग को अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। [पैरा 37] [697-एफ-एच; 698-ए-बी]

1.4. इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति एक बार के उपयोग के बाद समाप्त हो जाती है। कानून और भाषा दोनों ही अपने विकास के तरीके में जैविक हैं। भारत में, ये विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की वैध आकांक्षाओं को स्वीकार करने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हो रहे हैं। भारतीय भाषा कानून कठोर नहीं बल्कि उदार हैं - इसका उद्देश्य भाषाई धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित करना है। 1989 के संशोधन अधिनियम में न तो धारा 3 को शामिल करना और न ही उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में उर्दू को सात उद्देश्यों के लिए दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना असंवैधानिक है। [पैरा 43,44][701-सी-एफ]

श्री नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (1975) 2 एससीसी 671 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

श्री बी. शिवा राव (परियोजना समिति के अध्यक्ष) द्वारा "भारत के संविधान का निर्माण-एक अध्ययन"; ग्रानविले ऑस्टिन द्वारा भारतीय संविधान-एक राष्ट्र की आधारशिला, नौवीं छाप, 2005; भारत का संवैधानिक कानून - एक आलोचनात्मक टिप्पणी (चौथा संस्करण) एच. एम. सीरवल द्वारा; भारत के संविधान पर टिप्पणी, खंड 9, 2011, आचार्य डॉ. दुर्गा दास बसु द्वारा; भारत का संवैधानिक कानून टी.के. द्वारा टोपे, तीसरा संस्करण, 2010 और "भाषा नीति और भाषाई संस्कृति" भाषा नीति का परिचय: हेरोल्ड शिफ़मैन द्वारा सिद्धांत और विधि (2006) - संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ:

(1975) 2 एससीसी 671 अनुपयुक्त ठहराया गया . पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 459/1997

सिविल विविध रिट याचिका संख्या 10313/1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.08.1996 से।

श्याम दीवान, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. आई.बी. गौड़, एस.एस. नेहरा, नीरज दत्त गौड़, पीयूष शर्मा, विक्रमजीत बनर्जी, राकेश कुमार, मेरुसागर सामंतरी, इम्तियाज अहमद और सुश्री नगमा इम्तियाज (मैसर्स इक्विटी के लिए) लेक्स एसोसिएट्स), अधिवक्तागण, अपीलकर्ता के लिए।

डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर.पी. मेहरोत्रा, विभु तिवारी, अभिनव के. मलिक, आशुतोष कुमार शर्मा, कमलेन्द्र मिश्रा, मो. इरशाद हनीफ, विश्वजीत सिंह, ए.एस. पुंडीर, अरिजीत सिंह, सलाहकार।, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर. एम. लोढ़ा, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. दिनांक 12.11.1951 को, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (यू.पी. अधिनियम संख्या XXVI, 1951) (संक्षेप में, "1951 अधिनियम') राजपत्र असाधारण में

प्रकाशित हुआ और लागू हुआ। 1951 यूपी विधान सभा द्वारा अधिनियम 1951 हिंदी में 27.09.1951 को और यूपी विधान परिषद द्वारा 29.09.1951 को पारित किया गया। इसे 05.11.1951 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। हिंदी को भाषा के रूप में अपनाने के प्रावधान के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 1951 अधिनियम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों और अन्य मामलों के लिए उपयोग किया जाता है।

2. 1951 अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

2. हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा होगी - संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देवनागरी लिपि में हिंदी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से प्रभावी होगी। राजपत्र, इस संबंध में नियुक्त, निम्नलिखित के संबंध में उपयोग की जाने वाली भाषा होगी: -

(ए) (i) संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश।

(ii) भारत के संविधान के तहत या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, नियम, विनियम और उपनियम, और

(बी) राज्य के सभी या कोई आधिकारिक उद्देश्य; और उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं।

1969 का यूपी अधिनियम संख्या 9 द्वारा उपरोक्त धारा 2 में एक परंतुक जोड़ा गया था। इसमें लिखा है, "बशर्ते राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के उपयोग की अनुमति दे सकती है।"

3. 07.04.1982 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1982 नामक एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश की धारा 2 में प्रावधान है कि 1951 के अधिनियम में, धारा 2 के बाद, निम्नलिखित धारा (धारा 3 मानी जाएगी) डाली जाएगी:

उर्दू भाषी लोगों के हित में, अनुसूची में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए हिंदी के अलावा उर्दू भाषा का उपयोग दूसरी भाषा के रूप में किया जाएगा।

अध्यादेश की धारा 3 में प्रावधान है कि मूल अधिनियम में, धारा 3 के बाद, जैसा कि अध्यादेश द्वारा डाला गया है, निम्नलिखित अनुसूची डाली जाएगी:

1. जनता के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत उर्दू में मनोरंजक आवेदन।

2. पंजीकरण के लिए प्रस्तुत उर्दू में दस्तावेज़ों को उनकी हिंदी प्रति के साथ प्राप्त करना।

3. महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम एवं अधिसूचनाओं का प्रकाशन।

4. महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन।

5. गजट का उर्दू में अनुवाद।

4. उपरोक्त अध्यादेश को उ.प्र. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। राजभाषा (संशोधन) (3) अध्यादेश, 1983 (उ.प्र. अध्यादेश 44 सन् 1983)। यूपी की संवैधानिकता 1983 के अध्यादेश संख्या 44 को वर्तमान अपीलकर्ता यूपी हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा रिट याचिका संख्या 285 /1984 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के समक्ष रखा गया था। इस रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अलग-अलग निर्णयों द्वारा खारिज कर दिया था।

5. 07.10.1989 को, उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (यू.पी. अधिनियम संख्या 28, 1989) (संक्षेप में, "1989 संशोधन अधिनियम") लागू हुआ। विधान मंडल द्वारा 1989 संशोधन अधिनियम यूपी विधान मंडल द्वारा 1951 अधिनियम में संशोधन करेगा के लिये किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा, 1951 के अधिनियम में धारा 2 के बाद धारा 3 को शामिल किया गया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उद्देश्यों के लिए उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रदान किया गया था।

6. निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, राज्य सरकार ने 07.10.1989 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित सात उद्देश्यों के लिए उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया:

1. याचिकाओं और आवेदनों पर उर्दू में विचार करना और उनके उत्तर उर्दू में देना,

2. पंजीकरण कार्यालय द्वारा उर्दू में लिखे दस्तावेज़ प्राप्त करना,

3. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन,

4. सरकारी आदेशों और सार्वजनिक महत्व के परिपत्रों को उर्दू में भी जारी करना,

5. महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन,

6. राजपत्र का उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित करना,

7. उर्दू में महत्वपूर्ण साइनपोस्टों की प्रदर्शनी।

7. अपीलार्थी, यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन (सिविल अपील संख्या 459/1997), जिसने यूपी की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 285 /1984 दायर की थी। 1983 के अध्यादेश संख्या 44 ने 1989 के संशोधन अधिनियम और अधिसूचना दिनांक 07.10.1989 को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की।

8. इस रिट याचिका की सुनवाई एस.एन. सहाय और डी. के. त्रिवेदी, न्यायाधिपतिगण की खंडपीठ ने की।

9. एस.एन. सहाय, न्यायाधिपति ने अपने फैसले में कहा कि 1989 का संशोधन अधिनियम और रिट याचिका में लगाई गई अधिसूचना अधिकार क्षेत्र से बाहर है और रद्द किए जाने योग्य है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में उर्दू के संबंध में कोई भी कानून बनाने से नहीं रोका जाएगा।

10. दूसरी ओर, डी.के. त्रिवेदी, न्यायाधिपति., एस.एन. सहाय न्यायाधिपति के विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा कि 1989 का संशोधन अधिनियम और रिट याचिका में मेरे द्वारा लगाई गई अधिसूचना संवैधानिक दोष से ग्रस्त नहीं है और रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

11. पीठ के सदस्यों के बीच मतभेद को देखते हुए, पीठ ने निम्नलिखित प्रश्नों को उनकी राय के लिए तीसरे न्यायाधीश के पास भेजने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखने का निर्देश दिया:

1. क्या विवादित अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 345 के अर्थ में वैध कानून कहा जा सकता है?

2. क्या आक्षेपित अधिसूचना अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त है?

3. क्या आक्षेपित अधिनियम और आक्षेपित अधिसूचना वैध और संवैधानिक हैं या अधिकारातीत हैं?

12. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के लिए मामले को तीसरे न्यायाधीश, ब्रिजेश कुमार, न्यायाधिपति, (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) के पास भेज दिया।

13. ब्रिजेश कुमार, न्यायाधिपति, ने उनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए:

(1) कि राज्य में उपयोग के लिए दूसरी भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए कानून बनाते समय, राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के प्रावधानों को एक साथ पढ़कर उन पर विचार करना होगा; हालाँकि, रिट याचिका संख्या 285/84 में डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर विवादित अधिनियम कानून का वैध हिस्सा है।

2) विवादित अधिनियम अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त नहीं है।

(3) प्रश्न संख्या (1) और (2) पर दिए गए उत्तरों के मद्देनजर, मुझे लगता है कि विवादित अधिनियम और अधिसूचना वैध और संवैधानिक हैं।

14. तीसरे जज द्वारा दिए गए जवाबों के आलोक में रिट याचिका पर उचित आदेश के लिए मामले को खंडपीठ के समक्ष रखा गया।

15. खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 16.08.1996 द्वारा रिट याचिका को इस प्रकार खारिज कर दिया:

विद्वान तृतीय न्यायाधीश माननीय ब्रिजेश कुमार न्यायाधिपति के विचार में उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 28 सन् 1989) में धारा 3 जोड़ते हुए उ.प्र. राजभाषा अधिनियम, 1951 को अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत

माना गया है। आगे यह माना गया है कि विवादित अधिनियम अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त नहीं है। विवादित अधिनियम के साथ-साथ अधिसूचना को वैध और संवैधानिक माना जाता है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। लागत के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

16. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 16.08.1996 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय द्वारा 27.01.1997 को अनुमति प्रदान की गई थी।

17. 02.09.2003 को, अपील को इस न्यायालय की 2-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने महसूस किया कि विवाद की प्रकृति और मामले में उत्पन्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि मामले की सुनवाई 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए।

18. तब यह मामला 29.10.2003 को 3 - न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन, न्यायालय की राय थी कि अपील को 5 - न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 की व्याख्या के संबंध में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इस तरह ये अपील हमारे सामने आई है.

19. संविधान का भाग आधिकारिक भाग XVII से संबंधित है। इसमें चार अध्याय हैं, अध्याय I संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है, अध्याय II और अध्याय 4 संघ की भाषा से संबंधित है, अध्याय II, अध्याय III और अध्याय 4 क्षेत्रीय भाषाओं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा से संबंधित है और क्रमशः विशेष निर्देश।

20. यहां संविधान के भाग XVII के संबंध में प्रमुख लेखकों के विचारों पर संक्षेप में ध्यान देना उचित होगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि संविधान सभा में सबसे गहरा विवाद राजभाषा को लेकर था। श्री बी. शिवा राव (परियोजना समिति के अध्यक्ष) ने "द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन-ए स्टडी" में लिखा है: "इस मुद्दे ने इतनी गर्मी पैदा की और ऐसी हिंसक भावनाओं को जन्म दिया कि शुरू से ही इसे सभा में सीधी चर्चा से बाहर रखना जरूरी समझा गया। नेताओं ने इसे सामान्य सहमति के आधार पर निपटाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अक्सर ऐसा लगता था कि समझौता संभव नहीं होगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंत तक ऐसा नहीं हो पाया था कि किसी तरह का समझौते पर पहुंचा जा सकता है।" इस खंड के अध्याय 26 में, यह आगे दर्ज किया गया है:

संविधान सभा के उद्घाटन से ही भाषा के मुद्दे पर भावनाएँ प्रबल रूप से विकसित हुईं। हालाँकि, यह हिंदी बनाम उर्दू या हिंदी बनाम हिंदुस्तानी विवाद नहीं था जो इस समय उठाया गया था; इस बात पर आम सहमति थी कि राष्ट्रभाषा का नाम हिंदुस्तानी हो सकता है। जब प्रक्रिया के नियमों पर एक समिति के गठन का प्रश्न पर चर्चा की गई, आर. वी. धुलेकर ने एक संशोधन पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि समिति को अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी में नियम बनाने चाहिए। सभापति ने उनसे अंग्रेजी में बोलने का अनुरोध किया, क्योंकि कई सदस्य हिंदुस्तानी नहीं समझ सकते थे; लेकिन धुलेकर ने न केवल हिंदुस्तानी में बोलने पर जोर दिया बल्कि यह टिप्पणी की कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वे विधानसभा के सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं। सभापति ने संशोधन को नियम से बाहर कर और आगे की सभी चर्चाओं पर रोक लगाकर चर्चा को छोटा कर दिया; लेकिन जब समिति की रिपोर्ट चर्चा के लिए आई तो यह मुद्दा फिर से उठ गया। समिति ने सिफारिश की कि विधानसभा में कामकाज हिंदुस्तानी (हिंदी या उर्दू)

या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष को इन भाषाओं से अपरिचित किसी भी सदस्य को अनुमति देने की अनुमति दी गई। विधानसभा को अपनी मातृभाषा में संबोधित करें। सभा के आधिकारिक रिकॉर्ड उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में रखे जाने थे।

21.. भारत के संविधान के निर्माण के भाग IV में - चुनिंदा दस्तावेज़, अध्याय 13 राजभाषा से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। उसमें कहा गया है कि न तो संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे में और न ही मसौदा समिति द्वारा तय किए गए संस्करण में आधिकारिक भाषा से संबंधित कोई प्रावधान था, लेकिन उनमें भाषा या केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं के प्रावधान थे। संविधान के मसौदे पर सामान्य चर्चा के दौरान भाषा का मुद्दा प्रमुखता से उठा; और बहस के दौरान विकसित हुए तीव्र मतभेदों से यह पता चला कि प्रश्न ने किस हद तक भावना उत्पन्न की थी। अगस्त, 1949 के अंत में, मुंशी और गोपालस्वामी अय्यंगार ने मसौदा संविधान में शामिल करने के लिए विस्तृत मसौदा समझौता प्रावधानों को तैयार किया। मुंशी और गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा तैयार राजभाषा प्रावधानों के मसौदे जैसा कि प्रारूप समिति द्वारा संशोधित किया गया था, में चार अध्याय थे, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा आदि और विशेष निर्देश।

22. ग्रानविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान आधारशिला एक राष्ट्र में मुंशी-अय्यंगार फार्मूले को आधे-अधूरे मन से किया गया समझौता बताया है। उनका कहना है कि यह उन विचारों के बीच समझौता था जो आसानी से सुलहयोग्य नहीं होता था। इस सूत्र के पीछे दो मूल सिद्धांत थे, एक "हमें भारत की किसी एक भाषा को पूरे भारत की सामान्य भाषा के रूप में चुनना चाहिए"। दूसरा सिद्धांत यह था कि "सभी आधिकारिक संघ उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंक वही होने चाहिए जिन्हें

भारतीय अंकों के अखिल भारतीय रूपों के रूप में वर्णित किया गया है।" विधानसभा के सदस्यों ने मुंशी-अय्यंगार फॉर्मूले के पक्ष में मतदान किया.

23. एच. एम. सीरवई ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया - ए क्रिटिकल कमेंटरी (चौथा संस्करण) में भाषा के मुद्दे का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण भी दिया है, जो संविधान के मसौदे पर चर्चा के दौरान फूटा । एच. एम. सीरवई का कहना है कि हमारे संविधान में संघ को दिए गए स्थान को ध्यान में रखते हुए, संघ की आधिकारिक भाषा के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। अंग्रेजी और हिंदी के बीच अंतर स्पष्ट करते हुये, और दूसरी ओर अनुसूची VIII में उल्लिखित अन्य भाषाएँ, विद्वान लेखक कहते हैं:

अंग्रेजी विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा का वास्तविक माध्यम थी और है। संविधान और राजभाषा अधिनियम ने भारत संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग जारी रखा है। इसलिए, ऐतिहासिक कारणों से और स्पष्ट संवैधानिक और विधायी प्रावधानों के कारण, अंग्रेजी अपने आप में एक वर्ग में खड़ी है। हिन्दी भी अपना एक स्थान रखती है। यह भारत संघ की आधिकारिक भाषा है और संविधान का विचार है कि इसे धीरे-धीरे अंग्रेजी का स्थान लेना चाहिए। अत: हिन्दी भी अपने आप में एक वर्ग में है। लेकिन अनुसूची VIII में उल्लिखित अन्य भाषाएँ एक अलग पायदान पर खडी है माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बनाए रखना उचित है और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाना ऊपर बताए गए कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि लोगों के बड़े समूहों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषाएँ भी होंगी जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनने में सक्षम हैं। चूँकि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल, मलयालम और उर्दू है, इसलिए शिक्षा के माध्यम के रूप में इनमें से एक या अधिक भाषाओं के चयन को छोड़कर इसे उचित

ठहराना मुश्किल होगा। दूसरों का, यदि चयन का सिद्धांत यह है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए।

24. आचार्य डॉ. दुर्गा दास बसु ने भारत के संविधान, खंड 9, 2011 पर अपनी टिप्पणी में भाग XVII पर उप-शीर्षक "एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता" के तहत चर्चा करते हुए कहा कि संविधान निर्माता एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने में विफल रहे। भारत की राष्ट्रभाषा और संविधान में जो प्रावधान किया गया है, यह मुख्य रूप से विधि दावो के बीच एक समझौता है। इसके बाद डॉ. बसु का मानना है कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है वह राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि- (ए) संघ के लिए एक "आधिकारिक भाषा" है (अनुच्छेद 343-344); (बी) क्षेत्रीय आधिकारिक भाषाएं राज्य (अनुच्छेद 345-347); और (सी) आधिकारिक भाषा (ए) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए और (बी) संघ और राज्य में विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, उप-कानूनों के लिए स्तर। डॉ. बसु ने अपने ग्रंथ में टी.के. टोपे द्वारा रचित भारत के संवैधानिक कानून को उद्धृत किया है, जिसमें लेखक ने कहा है कि संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है; संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में निर्धारित नहीं किया है।

25. अब, दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद 345 और 347 की ओर मुड़ने का समय आ गया है, जो इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आए हैं कि क्या यह यूपी के लिए संवैधानिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत 1951 में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने के बाद विधान सभा ने 1989 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान की दलील यह है कि हिंदी भाषा की विशेष संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहां किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाता है, दो चीजें अनिवार्य रूप से पालन की जाती

हैं (एक) राज्य विधानमंडल को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने से रोका गया है और (दो) राज्य विधानमंडल को किसी अन्य आधिकारिक भाषा को अपनाने से रोका गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क इस आधार पर आधारित है कि संविधान का भाग XVII आधिकारिक भाषा के संबंध में पूरी योजना का गठन करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, भाग XVII की दो प्रमुख विशेषताएं हैं: हिंदी भाषा को एक विशेष दर्जा और भाषा के संवेदनशील और संभावित विभाजनकारी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सौंपी गई संतुलन की एक विशेष भूमिका।

26. श्री श्याम दीवान के तर्क से तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 345 का पाठ राज्य विधानमंडल को दो विकल्प देता है, एक, राज्य में उपयोग में आने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को अपनाना (विकल्प 1) और अन्य, हिंदी (विकल्प 2) और एक बार विकल्प 2 का प्रयोग करने पर राज्य विधानमंडल की शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि श्री श्याम दीवान के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि "या" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि विकल्प 1 राज्य के विधानमंडल के लिए तभी उपलब्ध होगा जब वह विकल्प 2 के लिए नहीं जाता है। एक बार राज्य विधानमंडल विकल्प 2 का प्रयोग किया है, और राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है, यह विकल्प 1 का रास्ता नहीं अपना सकता है। हमें विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। केवल इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया है और इसे राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, हमें नहीं लगता कि संविधान राज्य में उपयोग में आने वाली किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के राज्य विधानमंडल के विकल्प को रोकता है।

27. हमारे विचार से, अनुच्छेद 345 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हिंदी के अलावा राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाओं को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने से रोकता हो। यह केवल अनुच्छेद 345 में निहित प्रावधान को विकृत करने की कीमत पर हो सकता है। "हिंदी" से पहले आने वाले "या" शब्द का महत्व हिंदी के "प्रयोग में" होने की आवश्यकता को दूर करना है, जबकि "में" होने की आवश्यकता है। किसी भी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए "उपयोग" को अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए संतुष्ट होना होगा। हिंदी के लिए इस आवश्यकता को समाप्त करने का मतलब राज्यों में हिंदी को अपनाने को समाहित करना था। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि विशेष राज्य विधानमंडल को राज्य के भीतर अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने में अपनी शक्ति का त्याग करना होगा। अनुच्छेद 345 में अलग से हिंदी का उपयोग करने का उद्देश्य सभी राज्यों में हिंदी को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है, चाहे किसी विशेष राज्य में हिंदी का उपयोग हो या नहीं। अनुच्छेद 345 में कोई भी अन्य निर्माण संविधान द्वारा अपनाई गई भाषा समझौते में अनुचित हस्तक्षेप होगा।

28. संविधान का भाग XVII, जैसा कि इसकी योजना से पता चलता है, समायोजनकारी है। आख़िरकार, भाषा नीतियाँ निर्मित होती हैं और वे समय के साथ बदलती रहती हैं।"

29. अनुच्छेद 345 की स्पष्ट भाषा जो राज्य विधानमंडल को राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाओं को अपनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 345 की स्पष्ट भाषा से कोई भिन्न आशय प्रकट नहीं होता है। हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है और यदि राज्य

विधानमंडल हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लेता है तो वह शक्ति समाप्त हो जाती है। हमारे विचार में, राज्य विधानमंडल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए समय-समय पर अनुच्छेद 345 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के बाद, राज्य विधानमंडल के पास अनुच्छेद 345 के तहत कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं रह जाती है। नसीरुद्दीन मामले में इस न्यायालय के फैसले ने अनुच्छेद 345 के निर्माण के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन नहीं है।

30. हम थोड़ी देर बाद "विषय" अभिव्यक्ति पर विचार करेंगे, लेकिन यहां यह कहना पर्याप्त है कि कई राज्य विधानमंडल हैं जिन्होंने हिंदी के अलावा अन्य आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषा (भाषाओं) को अपनाया है जैसे कि बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। दिल्ली ने हिंदी के अलावा पंजाबी और उर्दू को भी अन्य आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में अपनाया है। जाहिर है, संवैधानिक अनुमति के बिना यह संभव नहीं होता।

31. पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति "राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अपनाएं" के संदर्भ में अनुच्छेद 345 में हिंदी को अलग से उल्लेखित करने की स्थिति अनुच्छेद 351 के संदर्भ में हिंदी को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए है, हालांकि यह राज्य में लोगों द्वारा बोली या उपयोग नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को राज्य के सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए राज्य में उपयोग में आने वाली किसी भी संख्या में भाषाओं को अपनाने में सक्षम बनाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसकी ओर से राज्य सरकार से मांग की ही जाये या यदि मांग है तो राज्य विधानमंडल राज्य में प्रचलित किसी भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाते हुए कानून नहीं बना सकता। यह अनुच्छेद 345 और 347 के बीच

विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। यदि किसी विशेष राज्य में हिंदी का उपयोग किया जाता है तो यह हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की राज्य की शक्ति या विवेक पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते ऐसी भाषा उस राज्य में उपयोग में हो'। अनुच्छेद 345 में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग बिना महत्व के नहीं है। यह इंगित करता है कि राज्य को राज्य में उपयोग में आने वाली भाषा या भाषा को अपनाने में विवेकाधिकार है और साथ ही हिंदी को भी। इस तरह के विवेक का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा जितनी बार उचित समझे उतनी बार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऐसी विधायी शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध अनुच्छेद 347 में है जिसे हम कुछ और चर्चा के बाद समझाएंगे।

32. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान का तर्क है कि संविधान का भाग XVII जिसका शीर्षक "आधिकारिक भाषा" है, एक पूर्ण संहिता के समान संविधान का एक स्व-निहित हिस्सा है। उनका कहना है कि भाग XVII के प्रावधान राजभाषा के संबंध में एक संपूर्ण योजना बनाते हैं। हम इस हद तक विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत हैं। उनका यह कहना भी सही है कि हिंदी भाषा को एक विशेष दर्जा प्राप्त है और विशेषकर भाग XVII में। इस संबंध में, अनुच्छेद 343(1), 344(2)(ए), 345, 346 परंतुक, 348(2) और 351 का संदर्भ सही ढंग से दिया गया है। संविधान में उपरोक्त प्रावधान, हमारे विचार में, हिंदी के लिये बड़े संवैधानिक चार्टर को निर्धारित करते हैं लेकिन यह स्थिति किसी भी तरह से अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाए गए निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि जहां किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाता है, वहां राज्य विधानमंडल को किसी अन्य आधिकारिक भाषा को अपनाने से रोका जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 345 में कुछ भी राज्य में हिंदी के अलावा, दूसरी आधिकारिक

भाषा के रूप में उपयोग में आने वाली किसी अन्य आधिकारिक भाषा को अपनाने पर रोक नहीं लगाता है।

33. यह सच है कि भाग XVII कई प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति (या उस मामले के लिए, 'संघ सरकार') की भूमिका निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रपति एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा की मांग का जवाब दे सकते हैं जहां अनुच्छेद 347 की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह निर्देश देने से पहले कि किसी विशेष भाषा को पूरे राज्य में या राज्य के किसी भी हिस्से में ऐसे उद्देश्य के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी जैसा कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट कर सकते हैं, राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि "राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी भाषा का उपयोग करना चाहता है।" उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए"। अनुच्छेद 350बी एक मशीनरी प्रदान करता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में मूल्यांकन कर सकते हैं। हालाँकि, हम अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि संविधान के भाग XVII में व्यवस्था यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि राज्य क्रमिक रूप से कई आधिकारिक भाषाओं की माँगों के आगे न झुकें और यह शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास आरक्षित है। (संघ कार्यकारी).

34. अनुच्छेद 345 में आने वाली अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अधीन" अनुच्छेद 345 को अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन नहीं बनाती है जैसा कि वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया है। "के अधीन..." अभिव्यक्ति का प्रभाव यह है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए मौजूदा निर्देशों के अधीन है, जब राज्य विधानमंडल अपना कार्य करता है। अनुच्छेद 345 के तहत शक्ति। एक बार अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी होने के बाद, यह राज्य विधायिका इस तरह के निर्देश के

साथ किसी भी तरह से छेडछाड करने के लिये स्वतंत्र नहीं है। दूसरे शब्दों में, राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति का प्रयोग किसी भी तरह से अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य की पूर्ण शक्ति केवल इसी सीमा तक सीमित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीमित सीमा को छोड़कर, यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 347 के अधीन है या उसके अधीन है। भाग XVII को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और, हमारे विचार में, अनुच्छेद 345 और 347 इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि इसे संघीय ढांचे और इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

35. अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति क्षेत्र पर कब्जा करने वाले अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ "अधीन ..." अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिबंधित है। ऐसे निर्देश के अभाव में, राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 345 के तहत इसकी शक्ति का किसी भी तरह से कार्य करने से नहीं रोका जाता है।

36. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देश के अभाव में, राज्य विधानमंडल के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राज्य में उपयोग में आने वाली भाषाओं में से किसी एक को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में कोई प्रतिबंध, संयम या बाधा नहीं है।

37. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल शक्ति से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। ये दोनों प्रावधान किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए कानून

बनाने या निर्देश जारी करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 347 में आवश्यकता, "किसी राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा के उपयोग को उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करने की इच्छा रखता है" अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल के लिए भाषा को अपनाते हुए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आधिकारित भाषा के तौर पर, जो कि राज्य में प्रचलित है। हमें नहीं लगता कि अनुच्छेद 347 की आवश्यकता को राज्य विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में पढ़ा जा सकता है। हम डी.के. द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हैं। त्रिवेदी, न्यायाधिपति ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल पर लगाई गई एकमात्र सीमा यह है कि उक्त भाषा राज्य में उपयोग में होनी चाहिए और इसके अलावा यदि अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया है तो वही बाध्यकारी प्रभाव होगा..."।

38. राज्य में हिंदी के अलावा एक या अधिक भाषाओं को अपनाने का मानदंड यह है कि वे भाषाएँ "राज्य में उपयोग में हों"। इस मानदंड को उस समय पूरा किया जाना चाहिए जब राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपना सकता है यदि ऐसी भाषा का उपयोग राज्य में नहीं किया जाता है। हालाँकि, राज्य विधानमंडल के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने में कोई बाधा नहीं है, भले ही कर्नाटक में हिंदी "प्रयोग में" न हो। इसका कारण भाषाई मुद्दे पर संवैधानिक समझौता और पूरे भारत में हिंदी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए हिंदी के लिए बड़े संवैधानिक चार्टर में पाया जाना है।

39. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि भाग XVII का अध्याय II राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल और केंद्रीय स्तर पर संघ कार्यकारी (राष्ट्रपति) को

शामिल करते हुए एक अद्वितीय द्वंद्व प्रस्तुत करता है। यह किसी राज्य में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए दो मार्ग प्रदान करता है; (ए) राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून को अपनाना; और (बी) भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक निर्देश। ये दोनों मार्ग एक-दूसरे के पूरक हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना सही है कि भारत का संविधान किसी भाषा को राज्य में आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए ऊपर बताए अनुसार दो मार्ग प्रदान करता है। हालाँकि, उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहाँ राज्य विधानमंडल ने किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य भाषा को मान्यता देने की मांग है जिसका उपयोग किसी राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा किया जाता है, संविधान किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए केवल एक विधि प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति के निर्देश के माध्यम से होती है, पूर्णतः सही नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 347 का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील सही हैं कि यदि किसी अन्य भाषा की मान्यता की मांग है जिसका उपयोग किसी राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति के निर्देश के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि, उनका यह कहना सही नहीं है कि किसी अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में नामित करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि विद्वान वरिष्ठ वकील के निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में राज्य विधानमंडल की शक्ति को प्रतिबंधित और सीमित कर देगा। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति में कटौती, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया है, न तो संवैधानिक रूप से उचित है और न ही यह आम तौर पर संविधान के भाग XVII की योजना और अनुच्छेद 345 और 347 के तहत दी गई योजना से उत्पन्न होती है। हम इस बात से

सहमत हैं कि ऐसी स्थिति में जहां किसी अन्य आधिकारिक भाषा की मांग होती है, अनुच्छेद 347 ऐसी मांग का जवाब देने के लिए संविधान में ज्ञात एकमात्र तरीका है। हमारे विचार से यह अनुच्छेद 345 और 347 की ग़लतफ़हमी है।

40. हमने ऊपर जो कहा है, उसमें हम अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 के साथ जुड़े उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से "घोषणा की मांग" दर्ज करता है। उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में समय-समय पर बनाया गया था", विवादित कानून अनुच्छेद 347 में विचारित स्थिति को कवर करता है और इसलिए, अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधायी शक्ति को लागू करना संवैधानिक रूप से खराब है।

41. अनुच्छेद 350 का एक साधारण पाठ दिखाएगा कि यह प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी भी कार्यालय में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील इस स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं कि राज्य कार्यकारिणी नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न भाषाओं को अपना सकती है। जाहिर है, तब राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 345 के तहत आने वाले क्षेत्र के संबंध में अपनी संवैधानिक शक्ति के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के बाद राज्य में उपयोग में आने वाली किसी भाषा या भाषाओं को अपनाकर और अधिक आधिकारिक भाषाओं को अपनाने के लिए कानून बना सकेगा। राज्य द्वारा विधायी शक्ति के प्रयोग को अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्ति का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्रभावी न हो।

42. संविधान का अनुच्छेद 367 एक व्याख्यात्मक प्रावधान है। अनुच्छेद 367 का खंड (1) पढ़ता है:

367. व्याख्या - (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सामान्य खंड अधिनियम, 1897, अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन, इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह भारत डोमिनियन के विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

43. संविधान में उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14 का प्रावधान संविधान की व्याख्या पर लागू होता है और इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि राज्य विधानमंडल समय-समय पर अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हमें अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली कि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 14 का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि भाग XVII की संवैधानिक योजना में एक अलग इरादा दिखाई देता है। हम पहले ही भाग XVII की संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 345 और 347 के दायरे और दायरे की व्याख्या कर चुके हैं। जिन कारणों से हमने ऊपर संकेत दिया है, हमें अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि शक्ति अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की क्षमता एक ही प्रयोग के बाद समाप्त हो जाती है। तर्क संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और अनुच्छेद 345 और 347 से उत्पन्न नहीं होता है। हमारे विचार में, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से अनुच्छेद 345 का अर्थ लगाना अनुचित होगा। ऐसा कहा जाता है कि कानून और भाषा दोनों अपने विकास के तरीके

में जैविक हैं। भारत में, ये विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की वैध आकांक्षाओं को स्वीकार करने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हो रहे हैं। भारतीय भाषा कानून कठोर नहीं बल्कि उदार हैं, जिसका उद्देश्य भाषाई धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित करना है।

44. हम मानते हैं, जैसा कि हमें करना चाहिए, कि न तो 1989 के संशोधन अधिनियम में धारा 3 को शामिल करना और न ही उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में सात उद्देश्यों के लिए उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना असंवैधानिक है।

45. अपील में कोई योग्यता नहीं है और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाता है।

विभूति भूषण बोस

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।